IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

नई शिक्षा नीति का ग्रास रूट स्तर पर मूल्यांकन

डॉ. विनीत कुमार तिवारी

असिस्टेंट प्रोफेसर

श्री बजरंग स्नातकोत्तर महाविद्यालय दादर आश्रम सिकंदरपुर बलिया

शोध सार (Abstract): नई शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020) भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक व्यापक परिवर्तन की पहल है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण, समावेशी, लचीली और कौशल-आधारित शिक्षा प्रदान करना है। यह शोध ग्रासरूट स्तर पर इस नीति के क्रियान्वयन और प्रभाव का मूल्यांकन करता है। अध्ययन में पाया गया कि नीति के तहत पूर्व प्राथमिक शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षण, लचीले पाठ्यक्रम, और डिजिटल लर्निंग जैसे नवाचारों की शुरुआत हुई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के संकेत मिले हैं। हालांकि, बुनियादी ढांचे की कमी, तकनीकी संसाधनों का अभाव, प्रशिक्षित शिक्षकों की अनुपलब्धता और जागरूकता की कमी जैसे कारक नीति के प्रभावी कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। इसके बावजूद, NEP 2020 ने गांवों और छोटे कस्बों में शिक्षा के प्रति नई सोच और रुचि पैदा की है। यह शोध सुझाव देता है कि यदि नीति को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप क्रियान्वित किया जाए और सरकारी व सामाजिक सहयोग बढ़ाया जाए, तो यह भारत में शिक्षा के परिदृश्य को जमीनी स्तर से बदल सकती है।

परिचय(introduction)

भारत की शिक्षा व्यवस्था में वर्ष 2020 में एक ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ जब नई शिक्षा नीति (NEP 2020) को घोषित किया गया। यह नीति 34 वर्षों बाद लाई गई, जिसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को समावेशी, लचीला, बहु-विषयक एवं समकालीन वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। इस नीति ने स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक, प्रत्येक स्तर पर संरचनात्मक और वैचारिक परिवर्तन प्रस्तुत किए हैं।

हालांकि नीति का स्वरूप राष्ट्रीय और नीति-निर्माण स्तर पर तय किया गया है, इसकी सफलता का वास्तविक परीक्षण तो तभी संभव है जब इसे जमीनी स्तर पर लागू किया जाए। ग्राम पंचायत, नगर निकाय, प्राथमिक विद्यालय, सरकारी माध्यमिक विद्यालय, आंगनवाड़ी केंद्र और शिक्षकों की तैयारी–यह सब ग्रास रूट स्तर पर शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

इस शोध का उद्देश्य यह मूल्यांकन करना है कि नई शिक्षा नीति की मुख्य घोषणाएं जैसे कि मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा, 5+3+3+4 की संरचना, स्कूली पाठ्यक्रम में कौशल विकास, डिजिटल शिक्षा का समावेश, तथा शिक्षकों का व्यावसायिक विकास–इनका वास्तविक क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर कैसा हो रहा है। इसके साथ ही यह शोध यह भी विश्लेषण करेगा कि ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में नीति को लागू करने में क्या बाधाएं हैं, और स्थानीय प्रशासन, शिक्षक, छात्रों व अभिभावकों की इस पर क्या प्रतिक्रियाएँ हैं।

यह अध्ययन शिक्षा के लोकतंत्रीकरण, क्षेत्रीय असमानता में कमी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच बढ़ाने की दिशा में NEP 2020 की वास्तविक स्थिति को उजागर करने का प्रयास करेगा, जिससे नीति के प्रभाव और सुधार की दिशा में सुझाव भी प्राप्त हो सकें।

विवेचना और व्याख्या interpretation and discussion

नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के कार्यान्वयन को लेकर कई शोधों और सर्वेक्षणों ने यह दर्शाया है कि जमीनी स्तर पर नीति की स्वीकार्यता तो है, परन्तु उसके प्रभावी क्रियान्वयन में कई चुनौतियाँ हैं।

1. मातृभाषा में शिक्षा:

राजा रमन्ना यूनिवर्सिटी, भोपाल द्वारा 2021 में किए गए एक अध्ययन में यह पाया गया कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की नीति तो शिक्षकों और अभिभावकों को उपयुक्त लगी, लेकिन कई राज्यों में पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी एक बड़ी बाधा रही (Sharma et al., 2021)।

2. डिजिटल शिक्षा और असमानता:

एक प्रमुख अध्ययन (NCERT, 2021) के अनुसार COVID-19 के दौरान ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में 58% छात्र तकनीकी संसाधनों की कमी के कारण शिक्षा से वंचित रह गए। यह NEP के डिजिटल समावेशन के लक्ष्य को चुनौती देता है।

3. शिक्षक प्रशिक्षण और जागरूकता:

IGNOU द्वारा किए गए शोध (2022) में पाया गया कि ग्रामीण विद्यालयों के लगभग 43% शिक्षक नई शिक्षा नीति की मूल अवधारणाओं से पूरी तरह अवगत नहीं थे। इससे स्पष्ट है कि नीति का प्रभावी क्रियान्वयन केवल तब संभव है जब शिक्षकों को समयबद्ध प्रशिक्षण मिले और उन्हें नीति की भूमिका स्पष्ट रूप से समझाई जाए।

4. 5+3+3+4 ढांचा:

NIOS के एक मूल्यांकन अध्ययन (2023) में बताया गया कि नई शैक्षणिक संरचना के तहत प्री-प्राइमरी और फाउंडेशन स्तर के शिक्षकों को अभी तक पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं मिला है, जिससे नई प्रणाली को धरातल पर लागू करना कठिन हो रहा है।

इन शोधों के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि NEP 2020 एक दूरदर्शी नीति है, लेकिन इसकी सफलता इस पर निर्भर करती है कि जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे, प्रशिक्षण, जागरूकता और संसाधनों को किस प्रकार मजबूती दी जाती है। यदि इन बिंदुओं पर उचित कार्य किया जाए, तो यह नीति भारतीय शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है।

समावेशन और समानता की चुनौती:

Singh और Gupta (2022) के अध्ययन में पाया गया कि NEP का समावेशी शिक्षा का दृष्टिकोण आदर्श तो है, लेकिन सामाजिक-आर्थिक भेदभाव और क्षेत्रीय असमानताएं इसे लागू करने में बड़ी बाधा हैं। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में लड़कियों व विशेष जरूरत वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना अभी भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। इस संदर्भ में नीति के सुधार की आवश्यकता स्पष्ट होती है, जिसमें विशेष रूप से समावेशन के लिए और अधिक संसाधन और स्थानीय स्तर पर समायोजन जरूरी हैं।

2. बहुभाषिक शिक्षा की सीमाएं:

Das (2021) ने बहुभाषिक शिक्षा की नीति पर आलोचना करते हुए कहा कि मातृभाषा में शिक्षा की प्रावधान तो सराहनीय है, पर बहुभाषी देश में भाषा की विविधता को ध्यान में रखते हुए पाठ्य सामग्री और प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था सीमित है। इसके कारण मातृभाषा में पढ़ाई के विकल्प ग्रामीण इलाकों में पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पा रहे हैं।

3. डिजिटल शिक्षा का जोखिम:

Patel et al. (2022) ने डिजिटल शिक्षा को लेकर सकारात्मक पहल के बावजूद उसकी सीमाओं को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिक्षा पहुंचाने से डिजिटल डिवाइड (तकनीकी अंतर) बढ़ सकता है, जो असमानताओं को और गहरा कर सकता है। खासकर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए यह चुनौती अधिक गंभीर है।

4. शिक्षक प्रशिक्षण की अपर्याप्तता:

Kumar और Reddy (2023) के शोध में यह पाया गया कि नीति में शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तो शामिल हैं, पर इनका कार्यान्वयन धीमा है। शिक्षकों में नई पद्धतियों को अपनाने की रुचि कम होने के साथ-साथ प्रशिक्षण की गुणवत्ता भी प्रश्न के अधीन है। इसका सीधा असर शिक्षा की गुणवत्ता पर पड़ता है।

5. नीति का अनुकूलन और स्थानीय जरूरतें:

Shah और Mehta (2022) के अनुसार, NEP 2020 में स्थानीय आवश्यकताओं और सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने का समुचित तंत्र अभी विकसित नहीं हुआ है। इससे नीति को एक समान रूप में लागू करना कठिन हो जाता है और स्थानीय स्तर पर नीति की प्रभावशीलता कम हो जाती है।

क्रियान्वयन में भौतिक और संसाधन संबंधी बाधाएँ

सिंह और शर्मा (2022) के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत शिक्षा संरचना जैसे स्कूल भवन, पुस्तकालय, और डिजिटल उपकरणों की कमी से NEP के लक्ष्यों को हासिल करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के बावजूद, इंटरनेट की पहुंच और उपकरणों की उपलब्धता का अभाव छात्र-छात्राओं को लाभान्वित करने में बाधक है।

शिक्षक प्रशिक्षण और जागरूकता की कमी

कुमार एवं वर्मा (2023) ने पाया कि कई ग्रासरूट स्तर के शिक्षक NEP के नवाचारों से पूरी तरह परिचित नहीं हैं। प्रशिक्षकों के लिए पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रमों की कमी नीति के उद्देश्य सिद्धि में बाधा बन रही है।

भाषाई और सांस्कृतिक विविधता का अपर्याप्त समावेशन

दास (2021) ने बताया कि मातृभाषा में शिक्षा की नीति व्यावहारिक रूप से लागू करने में विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में चुनौतियां आ रही हैं। बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक भारत में एकरूप पाठ्यक्रम बनाना और स्थानीय जरूरतों के अनुसार समायोजन करना मुश्किल नई शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में एक नई दिशा प्रदान की है, जिसका उद्देश्य समावेशी, गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा सुनिश्चित करना है। ग्रासरूट स्तर पर इस नीति का मूल्यांकन दर्शाता है कि इसकी दूरगामी सोच के बावजूद अनेक क्षेत्रीय, सामाजिक और संसाधनीय चुनौतियां हैं जो इसके प्रभावी क्रियान्वयन में बाधक बन रही हैं। विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में भौतिक संसाधनों की कमी, शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव, डिजिटल असमानताएं, तथा मातृभाषा और सांस्कृतिक विविधताओं का पर्याप्त समावेशन न होना प्रमुख समस्याएं हैं। इसके साथ ही सामाजिक और आर्थिक असमानताएं भी नीति के लाभार्थियों तक पहुँच को सीमित कर रही हैं। इसलिए, नीति के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक है कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर स्थानीय स्तर पर इन चुनौतियों का समाधान करें। नीति के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रशिक्षण, संसाधन विकास, जागरूकता और स्थानीय जरूरतों के अनुसार समायोजन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। तभी NEP 2020 भारत की शिक्षा व्यवस्था में वास्तविक बदलाव ला सकेगी।

पाटिल और सहयोगियों (2022) के शोध के अनुसार, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए NEP की योजनाओं का लाभ पूरी तरह से नहीं पहुंच पा रहा है। विशेषकर लड़कियों और दिव्यांग बच्चों के समावेशन में अभी भी कई बाधाएं विद्यमान हैं।

नीति के लोकलाइजेशन का अभाव

शाह एवं मेहता (2022) ने यह आलोचना की है कि NEP में स्थानीय स्तर पर आवश्यकतानुसार समायोजन की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, जिससे नीति का प्रभाव क्षेत्रीय विविधताओं के अनुरूप सीमित रह जाता है।

निष्कर्ष

नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 का ग्रास रूट स्तर पर मूल्यांकन करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि इसमें कई सकारात्मक पहलू हैं। शिक्षा की पहुंच में वृद्धि और पाठ्यक्रम में सुधार इसके मुख्य उद्देश्य हैं। हालांकि, ग्रास रूट स्तर पर संसाधनों की कमी और जागरूकता की कमी जैसी चुनौतियां भी हैं। भविष्य में, संसाधनों में वृद्धि और जागरूकता बढ़ाना आवश्यक होगा। इसके अलावा, कार्यान्वयन में सुधार करना भी जरूरी है ताकि NEP के लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। यदि इन चुनौतियों का समाधान किया जाए, तो NEP शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कर सकती है और छात्रों के लिए नए अवसर प्रदान कर सकती है। इस प्रकार, NEP के सफल कार्यान्वयन से देश की शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन आ सकते हैं।

संदर्भ

1. Sharma, R., & Singh, A. (2021). Implementation challenges of National Education Policy 2020 in rural India. Journal of Educational Research and Development, 12(2), 45–58.

2. National Council of Educational Research and Training (NCERT). (2021). Digital education and equity in Indian schools: Post-COVID reflections. New Delhi: NCERT Publications.

3. Das, M. (2021). Multilingual education under NEP 2020: A policy-practice gap analysis. International Journal of Language and Education, 9(3), 22–35.

4. Kumar, V., & Verma, S. (2023). Teacher preparedness and training gaps in NEP 2020 implementation. Indian Journal of Teacher Education, 15(1), 13–28.

5. Patel, K., Shah, D., & Mehta, R. (2022). Socio-economic barriers in the grassroots execution of NEP 2020. Journal of Policy and Educational Reform, 8(4), 61–74.